सतीश रावत

बनाम

भारत का संघ

26 अगस्त, 2002

[न्यायाधिपति एस. राजेंद्र बाबू और न्यायाधिपति पी. वेंकटरामा रेड्डी]

सेवा कानूनः खेल कोटा के तहत नियुक्ति- न्यायाधिकरण की चुनौती,नियुक्ति रद्द करते हुए, योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने के लिए विभाग को एक निर्देश जारी किया-तदनुसार, एक और उम्मीदवार को नियुक्त किया गया-प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा समीक्षा और नई याचिकाएं खारिज कर दी गईं-रिट याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई, चूंकि पूरा अभिलेख न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं रखा गया, इससे उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका - इन परिस्थितियों में, पहले नियुक्त व्यक्ति, जिसकी सेवाएं न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में समाप्त कर दी गई थीं, को वेतन की उचित सुरक्षा के साथ बहाल किया जाएगा, यदि आवश्यक हो तो एक सृजित कर अधिसंख्य पद-न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसार एक अन्य उम्मीदवार की नियुक्ति में भी बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

सीमा शुल्क विभाग ने लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और फील्ड ट्रायल आयोजित करने के बाद स्पोर्ट्सकोटा के तहत निरीक्षकों की नियुक्ति की। एक उम्मीदवार को "फुटबॉल" श्रेणी के तहत नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप लगाया कि अपीलकर्ता फील्ड टेस्ट में असफल रहा था, और फिर भी उसे नियुक्त किया गया था; और प्रतिवादी, हालांकि फील्ड टेस्ट में योग्य था, उसका चयन नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया और विभाग को योग्यता के आधार पर चयन करने का निर्देश जारी किया और अपीलकर्ता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह फील्ड टेस्ट में असफल रहा था। तदनुसार, विभाग ने एक अन्य उम्मीदवार का चयन किया, प्रतिवादी संख्या 3 व्यथित, अपीलकर्ता ने इस आधार पर एक समीक्षा याचिका दायर की कि विभाग ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए थे और इसलिए उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया था। न्यायाधिकरण ने समीक्षा याचिका के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा दायर एक नई याचिका को भी खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका भी खारिज कर दी गई। इसलिए यह अपील की गई ।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. न्यायाधिकरण के समक्ष राज्य द्वारा दायर दस्तावेजों में फील्ड टेस्ट तक उम्मीदवारों की मेरिट सूची का उल्लेख किया गया था। बाद में,

कोच के सहयोग से आधिकारिक टीम द्वारा फील्ड टेस्ट में प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नियुक्ति प्राधिकारी ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी क्रमांक 3 का चयन किया। इस बीच, न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किया और प्रतिवादी नंबर 3 ने अपीलकर्ता को विस्थापित कर दिया। न्यायाधिकरण ने माना कि उसके समक्ष रिकॉर्ड के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 3 अपीलकर्ता के बहिष्कार पर विचार करने का हकदार था। यदि न्यायाधिकरण के समक्ष पूरा रिकॉर्ड रखा गया होता तो उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इस मामले में जो गड़बड़ी हुई उसके लिए विभाग पूरी तरह से दोषी है. (674-बी-डी; 675-ए]

1.2. विभाग द्वारा पहले किए गए चयन के अनुसार, अपीलकर्ता ने एक निश्चित अवधि को छोड़कर लगभग 8 साल और 7-1/2 महीने तक काम किया था। खेल कोटा के तहत किसी भी पद पर चयन के लिए अपीलकर्ता की उम्र अब अधिक हो गई है। ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश पारित करने के समय उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर, अपीलकर्ता को विभाग द्वारा विचार से बाहर रखा गया था और अंक हासिल करने में अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 के बीच अंतर दिखाना बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि दोनों ने लिखित परीक्षा में एक अंक के अंतर के साथ लगभग समान अंक प्राप्त किए और साक्षात्कार में बड़ा अंतर था। जहां तक फील्ड टेस्ट का सवाल है, उसके परिणाम उम्मीदवारों की क्षमता के अनुसार बहुत स्पष्ट नहीं थे क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 फुटबॉल के खेल में

दो अलग-अलग श्रेणियों में आते थे, जिसके लिए विभाग खिलाड़ियों की भर्ती करना चाहता था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता की नियुक्ति उचित है। (674-ई-जी]

2. मामले की परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, और विभाग के लिए अपीलकर्ता को एक पद प्रदान करना उचित होगा और यदि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा पद सृजित किया जाएगा। नियमित रिक्ति उत्पन्न होने पर अधिसंख्य आधार को समाहित किया जाएगा। हालाँकि, अपीलकर्ता उस अवधि के लिए किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा जब उसने काम नहीं किया था। उसे उस पद पर उसी आधार पर नियुक्त किया जाए जिस आधार पर वह मूल रूप से नियुक्त किया गया था और उसे वेतन वृद्धि का उचित लाभ दिया जाए और उसका वेतनमान तय किया जाए। सेवा से मुक्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर उचित रूप से तय किया जाएगा। (675-बी, सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 133/ 2001

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.11.2000 से जो कि सी.डब्ल्यू.पी. 2000 की संख्या 15858 में पारित किया गया।

अपीलार्थियों की ओर से के. वी. विश्वनाथन, आर. के. माहेश्वरी, सुश्री रितु रस्तोगी और ऋषि माहेश्वरी।

प्रत्यर्थी के लिए राजू रामचंद्रन और पी. पी. मल्होत्रा, ब्रज किशोर मिश्रा, सुश्री अपर्णा झा, के. एन. नागपाल, राजीव नंदा और बी. के. प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति राजेंद्र बाबू द्वारा दिया गया था।

सीमा शुल्क कलक्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा खेल कोटा के तहत निरीक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। फुटबॉल श्रेणी के लिए दो पद निर्धारित किए गए थे। प्रतिभागियों को अर्हता प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी अंकगणित और सामान्य ज्ञान में लिखित परीक्षा देनी थी

लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों को साक्षात्कार का सामना करना पड़ा और फील्ड ट्रायल से भी गुजरना पड़ा। 4.6.1992 को, प्राप्त कुल आवेदनों में से 24 उम्मीदवारों ने फील्ड टेस्ट के लिए रिपोर्ट की और यह सूचित किया गया कि हमारे सामने अपीलकर्ता ने भी भाग लिया था लेकिन वह इसमें असफल हो गया था। हालाँकि, उन्हें चयनित किया गया और इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि प्रतिवादी नंबर 3, जो लिखित परीक्षा के साथ-साथ फील्ड टेस्ट और साक्षात्कार में भी योग्य था, का चयन नहीं किया गया। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच [इसके बाद इसे 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया जाएगा] के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया। 6.6.2000 को दिए गए एक आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया और विभाग को रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया गया कि कौन सा उम्मीदवार अधिक मेधावी था और चूंकि अपीलकर्ता फील्ड टेस्ट में असफल

हो गया था, इसलिए उसके नाम पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 3 का चयन किया गया और उसे इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। अपीलकर्ता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में कहा गया था कि विभाग ने जानबूझकर अपीलकर्ता के चयन के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड को रोक दिया था और चूंकि विभाग प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया था और प्रतिवादी नंबर 3 ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1998 तक कार्यवाही। न्यायाधिकरण के समक्ष यह आधार उठाया गया कि श्री मंजीत सिंह को खेल कोटा के तहत चुना गया था; विभाग प्रतिवादी संख्या 3 के चयन को उचित ठहरा रहा था और क्षेत्र परीक्षणों के परिणामों को इस आधार पर रोक रहा था कि वे प्रासंगिक नहीं थे। न्यायाधिकरण द्वारा यह माना गया कि चूंकि वे नए आधार लेकर आ रहे थे, इसलिए समीक्षा की अनुमति नहीं थी। इसी आशय का एक और आवेदन दायर किया गया था, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिए जाने के बाद यह अपील दायर की गई है विशेष अवकाश द्वारा हमसे पहले।साक्षात्कार में अपीलकर्ता ने 62 अंक प्राप्त किए थे, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 3 ने 48 अंक प्राप्त किए थे; लिखित परीक्षा में अपीलकर्ता ने 79 अंक हासिल किए थे, प्रतिवादी नंबर 3 ने 80 अंक हासिल किए थे और फील्ड टेस्ट में अपीलकर्ता ने 203 अंक हासिल किए थे, जबकि प्रतिवादी नंबर 3 ने 212 अंक हासिल किए थे। अब

जो मामला हमारे सामने रखा जाना है वह यह है कि अपीलकर्ता एक गोलकीपर है, जबकि प्रतिवादी नंबर 3 एक डीप डिफेंडर था। ऐसा कहा जाता है कि फील्ड टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची तैयार की गई थी; न्यायाधिकरण के समक्ष राज्य द्वारा दायर दस्तावेजों में फील्ड टेस्ट तक उम्मीदवारों की उपरोक्त योग्यता सूची का उल्लेख किया गया था कि गोलकीपर की श्रेणी में अपीलकर्ता को नंबर 7 पर स्थान दिया गया था और एक अन्य उम्मीदवार सुशील कुमार को रैंक नंबर 10 दिया गया था, बाद में, इस पर एक रिपोर्ट आई। फील्ड टेस्ट में प्रदर्शन कोच और शीर्ष के सहयोग से आधिकारिक टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था इंस्पेक्टर के पद के लिए दूसरी सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम का उल्लेख किया गया था, फुटबॉल के खेल के लिए विभाग की आवश्यकता के अनुसार, दूसरी सूची में किसी भी गोलकीपर को सूचीबद्ध नहीं किया गया था, हालांकि, दोनों सूची अवलोकन के लिए प्रस्तुत की गई थी। चयन समिति के नियुक्ति प्राधिकारी ने अपीलकर्ता और श्री मंजीत सिंह का चयन किया। जैसा कि पहले कहा गया था, न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित करने के बाद, प्रतिवादी नंबर 3 ने अपीलकर्ता को विस्थापित कर दिया।

विभाग द्वारा दायर समीक्षा आवेदन में यह विशेष रूप से कहा गया था कि अपीलकर्ता और अन्य उम्मीदवारों के चयन के रिकॉर्ड, जिन्हें 1992-93 में खेल कोटा के तहत चुना गया था, अब उस विभाग द्वारा किए गए चयन के अनुसार पता लगाया जा सकता है, जहां अपीलकर्ता ने 1-9-

1992 से 7.6.2001 तक लगभग 8 साल और 7 महीने तक काम किया था 1.12.2000 से 12.1.2001 तक के ब्रेक को छोड़कर, अब वह खेल कोटा के तहत किसी भी पद के लिए चयन के लिए अधिक उम्र का है। न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित करने के समय उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर, अपीलकर्ता को विचार-विमर्श से बाहर कर दिया गया था और अंक हासिल करने में अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच अंतर दिखाना दोनों के मुकाबले ज्यादा नहीं है। लिखित परीक्षा में एक अंक के अंतर के साथ लगभग समान अंक प्राप्त किये थे और साक्षात्कार में बड़ा अंतर था। जहां तक फील्ड टेस्ट का सवाल है, उसके परिणाम उम्मीदवारों की क्षमता के अनुसार बहुत स्पष्ट नहीं थे क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 दो अलग-अलग श्रेणियों में आते थे, एक गोल कीपर के रूप में और दूसरा डीप डिफेंडर के रूप में। इस आधार पर अपीलार्थी की नियुक्ति उचित है।

प्रतिवादी संख्या 3 अपीलकर्ता को विस्थापित नहीं कर सकता था, लेकिन इसके लिए ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया आदेश. न्यायाधिकरण ने इसे इस आधार पर माना इससे पहले के अभिलेख में वह अपीलकर्ता के बहिष्कार पर विचार किए जाने का हकदार था। यदि न्यायाधिकरण के समक्ष पूरा अभिलेख रखा गया होता तो उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता था। अपीलकर्ता की नियुक्ति में जो गड़बड़ी हुई और उसका उचित समर्थन नहीं किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति के लिए विभाग पूरी

तरह से दोषी है। यदि अब प्रतिवादी नंबर 3 को अपीलकर्ता द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो उसे उखाड़ दिया जाएगा।

मामले की परिस्थितियों में हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार प्रतिवादी नंबर 3 की नियुक्ति में खलल नहीं डाला जाना चाहिए। हालाँकि, अब सामने आए मामले के विशिष्ट तथ्यों में, विभाग के लिए अपीलकर्ता को एक पद प्रदान करना उचित होगा और यदि ऐसा पद उपलब्ध नहीं है, तो नियमित रिक्ति उत्पन्न होने पर समायोजित करने के लिए अतिरिक्त आधार पर ऐसा पद सृजित किया जाएगा। हालाँकि, अपीलकर्ता उस अवधि के लिए किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा जब उसने काम नहीं किया था। उन्हें मूल रूप से 1992 में नियुक्त किए गए आधार पर पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें वेतन वृद्धि का उचित लाभ दिया जाना चाहिए और सेवा से मुक्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर उनका वेतनमान उचित रूप से तय किया जाना चाहिए।

इन निर्देशों के अधीन, अपीलकर्ता को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाए। तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

एस के एस अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।